लाजिस्टिक्स-वेयरहाउसिंग में निवेश को लीज पर रेलवे की भूमि

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा की उपस्थिति में इंवेस्ट यूपी व रेलवे के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए ● सौजन्य : रेलवे

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लाजिस्टिक्स के ढांचे के और मजबूत करने के लिए बुधवार को इन्वेस्ट यूपी व भारतीय रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत लाजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को भारतीय रेलवे की भूमि 35 वर्षों की लीज पर औद्योगिक या सर्किल दर के मात्र 1.5 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद और रेलवे के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, लखनऊ मंडल, रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह समझौता उत्तर प्रदेश को औद्योगिक शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोक भवन में एमओयू हस्ताक्षरित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि अच्छी कनेक्टिविटी उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। समझौते की शर्तों में यह अनिवार्य किया गया है कि कच्चे माल या तैयार वस्तुओं के परिवहन की कम से कम एक प्रक्रिया रेलवे मार्ग से की जाएगी।

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ ने बताया कि राज्य में भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार 16,000 किलोमीटर से अधिक लंबे रेलवे नेटवर्क का लाभ उठाकर एक मजबूत लाजिस्टिक्स ईकोसिस्टम विकसित कर रही है। वर्तमान में दादरी में मल्टी-माडल लाजिस्टिक्स हब और वाराणसी में देश का पहला फ्रेट विलेज विकसित किया जा रहा है।